reported by NABARD, during the last three years is indicated below:

1993-94	1994-95	1995- 96
1165	581	NIL

NABARD have further reported that information in respect of Andhra Pradesh for the above three years is nil. The State-wise information in respect of the remaining States is being collected by NABARD.

News Item Regarding Illegal Tax Collection

1720. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned 'Illegal tax collection is nothing short of a scandal: Chelliah' appearing in the Times of India dated November 16, 1996;

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto;

(c) the details of the action taken against the officials involved; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to improve tax administration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Taxes are collected under the provisions of Taxing statutes. In case the views of the tax collecting agencies are not upheld, that docs not make the collection illegal in itself warranting action against the officials.

(d) Improvement and modernisation of tax administration is an on going process. It is taken up on top[1] priority basis.

Prevalence of Hepatitis-B in Country

1721. SHRIMATI BASANTI SARMA:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the virus Hepatitis-B is playing havoc in the country;

(b) if so, what is the prevalence and incidence of Hepatitis-B in our country; and

(c) what steps are being taken to control Hepatitis-B?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) Available data indicate that about 3-5% of the population are having chronic hepatitis-B infection.

(c) An Expert Committee has given certain recommendations in regard to the introduction of Hepatitis-B under the immunization programme. It has been decided to immunize the hospital workers of central Government Hospitals in the first instance. In addition screening of donated blood for Hepatitis 'B', Promotion of safe sex behaviour and use of disposable syringes etc. are also undertaken.

World Bank Assistance for Family Planning to Gujarat

1722. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether any World Bank assistance requested by the Government of Gujarat for the Family Planning Programme during the year 1995-96;

(b) if so, the details of the assistance provided to the state so far;

(c) whether the State Government has utilised all the assistance during the above period; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) to (d) A World Bank assisted Indian Population Project-VII is already under implementation in the State. The Project commenced on 2-11-1990 and is scheduled to be closed on 31.12.1997. The project has an outlay of Rs.43.90 crores. Out of this, the State has so far incurred an expenditure of Rs.32.02 Crores. It is expected that the state would utilise the full project outlay within the project period.

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के रिक्त पडे पद

1723. **डा. वाई . लक्ष्मी प्रसाद :**
श्रीमती आनंदी ज. पटेल :

(क) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या गांवों में स्थित सरकारी अस्पतलों में चिकित्सकों के पद रिक्त पडे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार इस समस्या को हल करने के लिए क्या योजना बना रही है;

(घ) क्या सच है कि बहुत कम चिकित्सक सुदूर और अतंस्थ क्षेत्रों में सेवा करने को इच्छुक हैं, और

(ड) यदि हां, तो क्या नव-निर्युक्त चिकित्सकों को अनिवार्य रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम पाचं वर्षो के लिए भेजने हेतु कोई कार्यवाही की जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुछेक पर रिक्त पड़े हुए हैं।

(ख) से (ड) राज्यवार विवरण अनुपत्र में दिया गया है। (देखिए परिशिष्ट 180, अनुपत्र संख्या 43).

कुल मिलाकर डाक्टर अभिवृतीय समस्याओं और सुविधाओं के अभाव के कारण दूरस्थ और संतस्थ क्षेत्रों में सेवा करने के इच्छुक नहीं है।

राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकार इन केन्द्रो में डाक्टरों की भर्ती और तैनाती करती है। राज्य सरकारों की समय-समय पर सलाह दी जाती हैं कि यदि आवश्यक हो तो वे संविदा के आधार पर भी डाक्टरों की रिक्तियां करें।

मध्य प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से अस्पतालों की दशा सुधारने की योजनाएं

1724. **श्री राघव जी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में विश्व बैंक की सहायता से अस्पतालों की दशा में सुधार करने की योजना के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1996 के दौरान उपरोक्त प्रस्तावों के आधार पर मध्य-प्रदेश को कितनी धनराशि की विश्व बैंक सहायता प्रदान की गई हैं;

(घ) वर्ष 1997 के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि की ऐसी सहायता दिये जाने का विचार है, और

(ड) किन-किन योजनाओं पर इस प्रकार की सहायता राशि खर्च किये जानें की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरबानी) : (क) से (ड) मध्य प्रदेश सरकार ने 535 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजना स्थापित करने के लिए प्रारम्भ में विश्व बैंक सहायता करने के लिए प्रारम्भ में विश्व बैंक सहायता के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। बहरहाल, बैंक की अपेक्षाओं सहित विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सहित संबंधित राज्यों से कहा गया था कि वे अपने परियोजना प्रस्तावों में कांट-छांट करे ताकि ये परियोजनाएं अन्ततोगात्वा पूरी की जा सकें। ये परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं